International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM),
ISSN: 2455-6211, Volume 12, Issue 10, October-2024, Available online at: www.ijaresm.com

उत्तर प्रदेश में मानव विकास सूचकांक का विश्लेषण

प्रगति निगम[1], प्रो. गोपाल प्रसाद[2]

[1]सहायक आचार्य, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
[2]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय, गोरखपुर

----------**********----------

भूमिका

किसी राष्ट्र के मानव ही उस राष्ट्र की असली संपत्तिहैं।(हक,1990) मानव विकास एक बहुआयामी विकास का घोतक है, इसमें केवल आर्थिक वृद्धिहीशामिल नहीं है, बल्कि सामाजिक आदतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिक आराम और वास्तव में वे सभी परिस्थियों में वृद्धि सम्मिलित है जो एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण करती है। "आय एक साधन है जबकी मानव विकास एक ध्येय है"।

मानव विकास स्वस्थ पर्यावरण से लेकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पोंको सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्प में वृद्धिऔर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि कीप्रणाली है। इसीके संदर्भ में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था कि अगर किसी भी सरकार की कल्याणकारीयोजनाओं कामापन करना हो तो हमएचडीआई(HDI)यानि मानव विकासकोमाप के बता सकते हैं कि सरकार की योजनाएँ कितनी प्रासंगिक हैं।

मुख्य शब्द: उत्तर प्रदेश, मानव विकास,मानव विकास सूचकांक, जनगणना 2011

उत्तर प्रदेश में एचडीआई का विशेषण क्यों आवश्यक है-

भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुमानों को विभिन्न स्तरों पर नीतिगत निर्णयों के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे वृहद राज्यों में व्याप्त सामाजिक और स्थानिक विषमताओं को देखते हुए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थिर जिलों के बीच मानव विकास स्थिति का विशेषीकरण करना और भी महत्तवपूर्ण हो जाता है।

इसी के संदर्भ में रस्किन बॉन्ड ने कहा था कि मैं एशिया यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में गया लेकिन जितनी विविधता एक अकेले उत्तर प्रदेश में है उतनी विविधता उनमेंसे किसी में भी देखने या अनुभव करने को नहीं है..... उत्तर प्रदेश अपने आप में एक दुनिया है....रस्किन बांड(मिश्रा,2010)
भारत की योजना आयोग ने वर्ष 2001 में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पेश की थी। मध्य प्रदेश राज्य पहली बार 1995 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करने के प्रयास की अगुवाईकरके भारत का अग्रणी राज्य बनकर उभरा।

उत्तर प्रदेश ने अपना पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 2003 में और दूसरा 2008 में तैयार कियाथा। दोनों ही रिपोर्ट को यूएनडीपी की पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया था, इन रिपोर्ट में न केवल उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय तुलना प्रस्तुत की गई बल्कि राज्य के जिलों की मानव विकास स्थितिकाविश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया था। यह विश्लेषण 1991,2001 और 2005 के लिए किया गया था।महाराष्ट्र 2012, मिजोरम 2013 और दिल्ली सरकारें 2013 को अपने एचडीआर के साथ आईं जिसमें यूपी के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारों के लिए

अपने एचडीआरकोनवीनतमआँकड़ों के अनुसार अपडेट करने की चुनौती पेश की।(मौर्य,सपनाएण्ड खरे, उत्तर प्रदेश में मानव विकास पेज नं-263)खंड 1, संख्या 4, दिसंबर 2015.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव विकास सूचकांकअधिक महत्वपूर्ण साबित होइसके लिए डिसएग्रीगेटेड मानव विकास सूचकांक अधिक उपयुक्त है।इवानोव और पेलेह (2011) नेतर्क दिया कि यह डिसएग्रीगेटेड नीति निर्माता को उप-राष्ट्रीय वास्तविकताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए आवश्यक है। डिसएग्रीगेटेडएचडीआई अंतर-क्षेत्रीय तुलना की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय अनुमानों के साथ उप-राष्ट्रीय या क्षेत्रीय तुलना की तुलना में अधिक न्यायसंगत है।डिसएग्रीगेटेड HDI यह तय करने में भी मदद करता है कि किस जिले में और किनकारण और किन संकेतकों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। (इवानोव और पेलेह,2011; कटोच, 2003; डे ला टोरे और मोरेनो, 2010).

मानव विकास सुचंकांक के घटक-

मानव विकास एक बहुआयामी विकास का संकेत है इसमें केवल आर्थिक विकास ही शामिल नहीं है बल्कि सामाजिक आदतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिक आराम और वास्तवमेंउनपरिस्थितयों में वृद्धि सम्मिलित है जो एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण करती हो। किसी भी राष्ट्र का विकास मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है, प्रथम प्राकृतिकसंसाधन और द्वितीय मानवीय संसाधन। अत: किसी भी देश का विकास सर्वोत्तममानव संसाधनके विकास के अभाव में संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब मानव संसाधन पूर्ण कुशल, प्रशिक्षित, स्वस्थ और उत्साहपूर्ण हो। इसके अभाव में उत्थान के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाएगा।किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में अधिक महत्तापूर्ण है क्योंकि मानव इन प्राकृतिक संसाधनों में अपनी बौद्धिक योग्यता और कार्य कुशलताका प्रयोग करकेविकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रोफेसर वीकेआरबी राव के अनुसार-मानवीय कुशलता और दक्षता को विकसित करके ही आर्थिक विकास का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है। प्रसिद्ध अमेरिका अर्थशास्त्री शूल्जका कथन है कि हमारी आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानव पूंजी का विकास है और ऐसे किए बिना हमें व्यापक दरिद्रता और कठिन शारीरिक श्रम से मुक्ति नहीं मिल सकती।

1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट के साथ मानव विकास की दशा में एक नये ऐतिहासिक कदम की शुरुआत होती है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से जुड़े हुएअर्थशास्त्री मेहबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तथा सिगर हंस ने कहा कि मानव विकास सूचकांक तीनअवयव पर आधारित है

1-जीवन प्रत्याशा
2-शिक्षा
3- आय।

यह सूचकांक परम्परागत विकास मापक'आय'से हटकर विकास की दशाओं में हुए साकारात्मक वृद्धि कोमापने का प्रयास करता है। यह सूचकांक एक प्रकार का बैरोमीटर है जो मानव कल्याण के उत्थान में हो रहे परिवर्तन का मापन करता है तथा देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विकास की प्रगतिकी तुलानात्मक स्थिति प्रदर्शित करता है। मानव विकास का उद्देश्य मानवों में उनके ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, आर्थिक गरीबीऔर सामाजिक भेदभाव को दूर करउन्हें सक्षम,समर्थ और योग्य बनाना होता है। परन्तु स्वतंत्रता का उपभोग करने में कुछ लोगों पर बंधन लग जाती है क्योंकि वह गरीब हैं, बीमार हैं और निरक्षर हैं।

"मानव विकास की अवधारणा का आधार स्वतंत्रताऔर मुक्त विकास है"(UNDP 1990)। आर्थिक विकास और मानव विकास में मूल अंतर होता है जहां आर्थिक विकास का सारा फोकसआय बढ़ोतरी पर केन्द्रित होता है वहीं मानव विकास का ध्यान मानव जीवन के सभी आयामों के विकास करने से होता है। ये आयाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू होते हैं।

मानव विकास अनुक्रमणिका के घटक

1. जीवन प्रत्याशा :- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा की स्थिति –

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरूषों का प्रतिशत 52.29% है जबकि महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है। भारत की जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1947 में 32 वर्ष थी वर्तमान में बढ़कर 66.8 वर्ष हो गई है, (26 सितंबर, 2024, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) हालांकि भारत की जीवन प्रत्याशा अनुमानित गोबल औसत 72.6 वर्ष सेकाफी कम है,जबकी उत्तर प्रदेश में पुरूषों की जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.2 वर्ष ही है जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है।उत्तर प्रदेश भारत के सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर हैं। पुरूषों की जीवन प्रत्याशा भारत में सबसे ज्यादादिल्ली में 74.3 है, जबकी महिलाओंकी जीवन प्रत्याशासबसे ज्यादा 78 वर्ष केरल राज्य में है..(स्रोत - एसआरएस संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-19)।नवजात मृत्यु दर(IMR) 50 प्रति हजार जीवित जन्मों तक कम हो गई है।बजट 2024-25 के अनुसर यूपी में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा जन्म दर (25.1) उत्तर प्रदेश राज्य का है, जबकी भारत का औसत जन्म दर (19.6) है।

भारत का मृत्यु दर (6.0)है, जबकी उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर(6.5) भी भारत केऔसत से ज्यादा हैलेकिन अच्छी बात ये है कि उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर देश के कुछ अन्य राज्यों से अच्छाहैं, उदाहरण-छत्तीसगढ़(7.9), केरल(7.0), ओडिशा(7.3), पंजाब(7.2), हिमाचल प्रदेश(6.8)....अगर शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तोराष्ट्रीय औसत28 है परंतु उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 38 है।भारत के लगभग 80% विशेषज्ञ डॉक्टर शहरों में काम करते हैं।अगरग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम की बात जाये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक केंद्र है
(3055) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है (939),प्रदेश में शहरी जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार कार्यात्मक PHC के 36.7% U-PHC की कमी हैलेकिन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली में अधिक यू-पीएचसी मौजूद है। भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल में पलंग की उपलब्धता 3.96 कि विश्व औसत की तुलना में केवल 0.7 से थोड़ा अधिकपलंगउपलब्ध है।अगर लिंगानुपात की बात हो तो2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 भारत के लिंगानुपात 943 से कम है.उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर, आज़मगढ़ और देवरिया हैं, जबकी नवीनतम लिंगानुपात वाले हैं गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा हैं।उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष आयु समूह) वर्तमान में (902)हैं, जो वर्ष 2001 में 916 वर्ष का था, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात में सुधार हुआ है। राज्यमें अधिकतम और सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलेक्रमश: बलरामपुर और बागपत हैं। बजट 2023-24 में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्यमिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और स्वास्थ्य पर लगभग 1000 करोड़ रुपए आवन्टित किए गए हैं।

2. शिक्षा: साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात और शिक्षा की गुणवत्ता –

"एक बच्चा, एक शिक्षक, एक पुस्तक और एक कलम विश्व को बदल सकते हैं"। (मलाला यूसुफजई)

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.72% है जो भारत के अन्य राज्यों कीतुलना में 29वें पायदान पर है। जबकी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। (ओझा, एस.के.(2016) जनसंख्या एवं नगरीकरण,इलाहाबाद बौद्धिक प्रकाशन पृष्ठ संख्या 65-66.
प्राथमिकस्तरपरहिंदू मुस्लिमएवं अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की औसत साक्षरता 14.36 प्रतिशत है जबकी राष्ट्रीय साक्षरता 72.68 प्रतिशतएवं प्रादेशिक साक्षरता 67.68 प्रतिशत की अपेक्षा बहुत कम हैं। (अहमद एम.(2018) एक्सेस आफ मुस्लिम्स टू एजुकेशन इन यूपी, इण्डिया।

वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.27 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 69.72 हो गई है,मतलब आँकडों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।परंतु फिर भी विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं नीति आयोग के एक संयुक्त रिपोर्ट 'the success of our school, school education quality index'जिसमें देश के 20 बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता जांच के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ताअनुक्रमणिका 2016-17 की रिपोर्टमें उत्तर प्रदेश का स्थान रैंकिंग में सबसे नीचे, जबकी केरल, राजस्थान एवं कर्नाटक को क्रमश: 1,2,3 स्थान प्राप्त हुआ।एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली(U.D.I.S.E.)फ्लैश रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात स्थिति भारत में सबसे खराब है। यहां 39 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है जबकी राष्ट्रीयस्तर पर यह औसत 23:1 है, जबकी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपत 30:1 निर्धारित किया गया है। आँकड़ों के मुताबिक अभी भी 1.4 लाख शिक्षकों की कमी है। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2018) शिक्षा का अधिकार). अगर हम वर्ष 2024-25 के बजट को देखें तो बजट में सबसे ज्यादा रुपये का आवंटन प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए किया गया है और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री प्रशिक्षुप्रोत्साहनयोजनाके अंतर्गत100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया है।

3.जीवन स्तर: प्रति व्यक्ति आय, आर्थिकअसमानता –

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 68818 रुपएदर्जकी गई है, जो पहले क्रमशः 2016-17 में 52671, 2017-18 में 57944, 2018-19 में 62350, 2019-20 में 65666, और 2020-21 में 61666 थी। हालांकि अब भी उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत सेकाफी कम है। 2021-22में भारतकी प्रति व्यक्ति आय 150009 रुपये दर्ज है। दिल्ली, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड वगैरह राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रऔसत से अधिक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा प्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश सरकार की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक इस जिले में प्रति व्यक्ति आय 6.47 लाख रुपये है।राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का औसत 3.2% है जबकी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर का औसत 2.4% है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर गोवा की है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर त्रिपुरा की है। 2011 की जनगणना में स्लम की कुल आबादी 9.5% थी औरदेश की कुलस्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त है।मेरठ, आगरा और कानपुर नगर सर्वधिकस्लम आबादी वाले जिले हैं प्रदेश की कुलजनसंख्या में 3.12प्रतिशतजनसंख्या स्लम का है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश ने निश्चित रूप से अपने मानव विकास स्थिति में सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंगमें उत्तर प्रदेश 14वीं रैंक से दूसरीरैंक पर पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने “अचीवर्स” की श्रेणी प्राप्त की है।देश के कुल जीडीपी योगदान में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन 1980 के दशक में आर्थिक विश्लेषक आशीष बोस ने ‘बीमारू’नमक एक शब्दगढ़तेहुए एक पेपर प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सुची में शामिल किया था, क्योंकि उनका कहना था कि यूपी की संभावित आयु

संपूर्ण भारत की औसतसंभावित आयु से कम है, और इस राज्य के कारण संपूर्ण भारत की औसतसंभावित आयुकम होतीहै।आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की कुल जन्म जीवन प्रत्याशा 2014-18 में 69.4 थी, और उत्तर प्रदेश का 65.3 था, इसी के साथ 2016-20 में भारत की जन्म जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष थी और उत्तर प्रदेशका 66वर्ष,...आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश काप्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 93514 रुपये है, जो कि राष्ट्रीय औसतसे काम है,जबकि अपने पिछले वर्ष के 84125 रुपये से अधिक है। निष्कर्षतः ह्म कह सकते हैंकिआज़ादीके इतने वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश कोमानव विकासके लिये अनेक सुधारकरने की जरूरतहै।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. Department of Education Management Information System National University of Education Planning and Administration (2011-12) State of Alimentary Education in UP DISE -2011-12.
[2]. Ministry of Human Resource Department (2018), Right to Education
[3]. September 26,2024 Ministry of Health and Family Welfare.
[4]. Government of India:SRS Abridged Life Table 2015-19.
[5]. SRS Bulletin May 2022, Sample Registration System, Office of the Registrar General, India.
[6]. रावत अरविंद, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा: एक विश्लेषण।
[7]. ओझा, एस. के. (2016 जनसंख्या एवं नागरिकरण, इलाहाबाद, बौद्धिक प्रकाशन पृष्ठ संख्या -65-66.
[8]. अहमद, म.(2018). Access of Muslims to Education in UP, India.
[9]. Census 2011.
[10]. Maurya, N. K., Singh, S., &Khare, S. (2016). Human Development in Uttar Pradesh: A district level analysis. Social Science Spectrum, 1(4), 262-278.
[11]. UNDP(2005), Human Development Report 2005: Uttar Pradesh.
[12]. Upadhyay,M.(2015) Perspectives of growth in Uttar Pradesh (India).
[13]. Sen, Amartya, Development as Freedom,1999.
[14]. UP Budget 2024-26
[15]. Health Dynamics of India (Infrastructure and human resource 2022 -24) page no-13,22,118,119.